लोक प्रशासन में
उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration

2008 - 2009

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार

Department of Administrative Reforms and Public Grievances
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Government of India

विषय-सूची

1. वर्ष 2008-2009 के लिए पुरस्कार विजेता

(i) ढ़ाँचो का अतिक्रमण हटाना- सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना, जबलपुर, मध्य प्रदेश 1

(ii) नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी, बालाघाट, मध्य प्रदेश 2-3

(iii) औषधियों को किफायती बनाना, चित्तौड़गढ़, राजस्थान 4-5

(iv) नदी संयोजन परियोजना, जलगांव, महाराष्ट्र 6

(v) गर्भाशय कैंसर की जाँच, चेन्नई, तमिलनाडु 7

(vi) धान की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण, छत्तीसगढ़ 8-9

(vii) वन अधिकारों को मान्यता, मध्य प्रदेश 10-11

(viii) समन्वित करदाता आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस) 12-13

(ix) ''प्रोजेक्ट एरो''-भारतीय डाक की कायापलट 14-15

2. वर्ष 2007-08 के लिए पुरस्कार विजेता 16-18

3. वर्ष 2006-07 के लिए पुरस्कार विजेता 19-23

4. वर्ष 2005-06 के लिए पुरस्कार विजेता 24

CONTENTS

1. Awardees for the Year 2008-09

(i)	Removal of Encroachments of Structures – Maintaining Communal Harmony, Jabalpur, Madhya Pradesh	1
(ii)	Involvement of Community in Naxalite-affected Areas, Balaghat, Madhya Pradesh	2-3
(iii)	Making Medicines Affordable, Chittorgarh, Rajsthan	4-5
(iv)	River Linking Project, Jalgaon, Maharashtra	6
(v)	Cervical Cancer Screening, Chennai, Tamil Nadu	7
(vi)	Computerization of Paddy Procurement and Public Distribution System, Chhattisgarh.	8-9
(vii)	Recognition of Forest Rights, Madhya Pradesh	10-11
(viii)	Integrated Taxpayer Data Management System (ITDMS)	12-13
(ix)	Project Arrow – Transforming India Post	14-15

2. Awardees for the Year 2007-08 16-18
3. Awardees for the Year 2006-07 19-23
4. Awardees for the Year 2005-06 24

पहल – ढ़ाँचों का अतिक्रमण हटाना – सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना, जबलपुर, मध्य प्रदेश

पुरस्कार विजेता का नाम – श्री संजय दुबे, भा. प्र. से., तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश, जबलपुर, मध्य प्रदेश

सार्वजनिक सड़कों और भूमियों पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाए बिना धार्मिक प्रकृति के अतिक्रमणों को हटाना बहुत कठिन कार्य है। वर्ष 2005 में श्री संजय दुबे, तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश, जबलपुर द्वारा जबलपुर जिले में अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाया गया था। इस पहल के अधीन धार्मिक संरचनाओं को हटाने की रूपात्मकताओं पर निर्णय लेने के लिए शांति समिति की बैठकों के कई दौर आयोजित किए गए थे। शांति समिति के सदस्यों को विश्वास में लिया गया था और उच्च न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन में उनका सहयोग मांगा गया।

श्री संजय दुबे ने सामूहिक रूप और व्यक्तिगत रूप दोनों में धार्मिक गुरुओं और मत निर्माताओं से भी मुलाकात की तथा उन्हें कारण और प्रतिबद्धता स्पष्ट की। यद्यपि विभिन्न हित समूहों ने खुले रूप में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने में भय व्यक्त किया फिर भी वे कारणों से अवगत थे तथा उसके समर्थक थे। नामिती का सामर्थ्य ही था जिसने समुदायों की प्रतिभागिता सूचीबद्ध की।

लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किए बिना अथवा सांप्रदायिक सद्भाव में बाधा डाले बिना धार्मिक प्रकृति के 566 गैर-कानूनी संरचनाओं में से विभिन्न धार्मिक मतों के 311 संरचनाओं को सितम्बर, 2005 से जून, 2008 तक गिराया/पुनः स्थापित किया गया। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी हुई और जेएनएनयूआरएम तथा अन्य ऐसे ही स्कीमों के अधीन विकास कार्य सुविधाजनक हुए। अब नागरिक नए अतिक्रमणों को रोकने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

Category - Individual

Initiative - Removal of Encroachments of Structures - Maintaining Communal Harmony, Jabalpur, Madhya Pradesh

Name of the Awardee - Shri Sanjay Dubey, IAS, then Collector & District Magistrate, Jabalpur, Madhya Pradesh

Removal of encroachments of religious nature on public roads and lands without hurting religious sentiments of people is a very tough task. An anti-encroachment drive was undertaken in the Jabalpur district in 2005, by Shri Sanjay Dubey then Collector & District Magistrate, Jabalpur. Under this initiative, several rounds of meetings of the peace committee were held to decide the modalities of removal of religious structures. The members of the peace committee were taken into confidence and their cooperation solicited in the implementation of the orders of the High Court.

Shri Sanjay Dubey also called on the religious gurus and opinion makers, both collectively and individually, and explained to them the cause and commitment. Though the different interest groups feared to show their commitment in the open, they were aware of the cause and were supportive of it. It was the nominee's ability that enlisted the participation of the communities.

Out of 566 illegal structures of religious nature, 311 of different religious faiths were demolished / relocated during September 2005 to June 2008, without hurting the religious sentiments of the people or disrupting communal harmony. This brought down the number of road accidents and facilitated the development works under the JNNURM and other similar schemes. Citizens are now taking active part in preventing fresh encroachments.

पहल – नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी बालाघाट, मध्य प्रदेश

पुरस्कार विजेता का नाम – श्री गुलशन बामरा, भा. प्र. से., तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश, बालाघाट
मध्य प्रदेश

बालाघाट मध्य प्रदेश के नक्सल-प्रभावित जिलों में से एक हैं और यहां की विशेषता रोजगार के अवसरों में कमी रही है। जिला प्रशासन ने नागरिक-केंद्रित अधिशासन, विकास आयोजना के प्रति भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण और मजदूरी रोजगार, कृषि उत्पादकता और आजीविका के अवसरों जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के माध्यम से वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) कार्यान्वित करने का प्रयास किया।

श्री गुलशन बामरा, जिन्होंने वर्ष 2006 में 1.5 मिलियन की जनसंख्या वाले जिले का प्रभार ग्रहण किया, ने ऐसा सहक्रियात्मक प्रशासन लाने को प्राथमिकता दी, जो जनता-केंद्रित अधिशासन, एनआरईजीएस जैसी सरकारी प्रायोजित स्कीमों के एकीकृत कार्यान्वयन, संवेदी नीति निर्धारण आदि पर बल दें। जबकि एनआरईजीएस संपूर्ण देश में कार्यान्वित किया गया, बालाघाट में नामिती ने एनआरईजीएस के अधीन प्रारंभ की गई परियोजनाओं के साथ सड़क निर्माण, राज्य सरकार के जलसंभर कार्यक्रम तथा वार्षिक योजना निधि जैसे केंद्रीय स्कीमों के अधीन विकास धनराशि का प्रयोग एकीकृत किया। चूंकि विकास कार्यक्रम स्थानीय मांग के अनुसार तैयार किए जाते हैं और आगे पंचायत स्तर से उनका अनुवीक्षण किया जाता है, इसलिए हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए शिकायत पेटियां प्रदान की गई थीं और कार्यस्थलों में शिकायत रजिस्टर रखे गए थे।

तीन वर्षों में जिले में सड़क संपर्क 520 किलोमीटर से बढ़कर 2228 किलोमीटर हो गया। लगभग 28,000 हेक्टेयर नई भूमि सिंचाई के अधीन लाई गई। तेंदू पत्ता संग्रहण और बांस की कटाई जैसे कार्यकलाप पुनः प्रारंभ किए गए। वन उत्पादों से राजस्व संग्रहण वर्ष 2006-07 में 28 करोड़ रुपए से लगभग दुगुना होकर वर्ष 2008-09 में 55 करोड़

Initiative - Involvement of Community in Naxalite-affected Areas, Balaghat, Madhya Pradesh

Name of the Awardee - Shri Gulshan Bamra, IAS, then Collector and District Magistrate, Balaghat, Madhya Pradesh

Balaghat is one of the naxal-affected districts of MP and has been characterized by lack of employment opportunities. The district administration sought to implement the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) in 2006 through citizen-centric governance, participatory approach to development planning and addressing issues like wage employment, agricultural productivity and livelihood opportunities.

Shri Gulshan Bamra who took charge of the district with a population of 1.5 million in 2006, made it a priority to bring about a proactive administration that focused on people-centric governance, integrated implementation of government sponsored schemes like NREGS, sensitive policing, etc. While NREGS was implemented across the country, in Balaghat, the nominee integrated the use of development money under Central schemes such as road building, the state government's watershed programme and yearly plan funds, along with the projects taken up under NREGS. Since the development programmes were devised according to the local demand and monitored from the Panchayat level onwards, stakeholders' participation was ensured. Complaint boxes were provided and complaint registers were maintained at workplaces for quick disposal of complaints.

In three years, the road connectivity in the district increased to 2,228 kms from 520 kms. About 28,000 hectares of new land came under irrigation. Activities such as Tendu leaf collection and bamboo cutting were resumed. Revenues from forest produce nearly doubled from Rs. 28 crores in 2006-07 to Rs. 55 crores in 2008-09. Migration dropped from 4,217 in 2005-06 to

रुपए हो गया। वर्ष 2005–06 में प्रवासन 4217 से घटकर वर्ष 2008–09 में 2840 हो गया क्योंकि स्थानीय लोगों को अपने घर के समीप कार्य प्राप्त हो गया। यह एक जनता–केंद्रित कार्यक्रम था, जहां स्थानीय और सामाजिक हितों के सभी मुद्दों पर पुरुष और महिला सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से चर्चा हुई और लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिए गए। इस प्रकार, नामिती स्थानीय समुदाय को नक्सल प्रभाव से अलग करने और चहुँमुखी विकास सुनिश्चित करने में समर्थ हुए।

2,840 in 2008-09 as locals found work near their homes. It was a people-centric programme where all issues of local and social interests were discussed with the active participation of male and female members and decisions were taken in a democratic manner. Thus, the nominee was able to wean away the local community from the naxal influence and to ensure all-round development.

पहल – औषधियों को किफायती बनाना, चित्तौड़गढ़, राजस्थान

पुरस्कार विजेता का नाम – डॉ. समित शर्मा, भा. प्र. से., तत्कालीन जिलाधीश, चित्तौड़गढ़, राजस्थान

यह परियोजना दूरस्थ ग्रामीण गांवों में सामान्य दवाईयों की लागत कम करने के लिए प्रारंभ की गई। निजी दवा दुकानों में बेचे जाने वाले मूल्य के एक–चौथाई से भी कम पर सरकारी दवा दुकानों में गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराए जाने से उस तरीके में आमूल–चूल परिवर्तन कर दिया जिस तरीके से औषधियां और अन्य शल्यचिकित्सीय उपकरण राजस्थान राज्य के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राप्त, वितरित और बेचे जाते हैं।

कार्यान्वयन की मुख्य विशिष्टता जिला–व्यापी उचित मूल्य की दवा दुकानों की श्रृंखला के माध्यम से औषधियों तक पहुंच सुनिश्चित करना था, जो सरकारी अस्पतालों के ओपीडी और ''अंतरंग रोगियों'' तथा साथ ही आम जनता की सेवा करते हैं। इस पहल में चिकित्सकों से सामान्य दवाईयां निर्धारित करने का अनुरोध शामिल है। इन सामान्य दवाईयों की अधिप्राप्ति चिकित्सकों के एक दल द्वारा सुझाव दिए गए अनुसार की गई थी और कतिपय बहुत प्रतिष्ठित भेषज (फार्मास्यूटिकल) कंपनियों को औषध अधिप्राप्ति भागीदारों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इस प्रकार प्राप्त दवाईयों को सरकारी–नियंत्रणाधीन दवा की दुकानों के माध्यम से न्यूनतम खुदरा मूल्य से बहुत कम मूल्य (एक–चौथाई मूल्य पर) पर वितरित किया गया था और फिर भी 20 प्रतिशत का लाभ अर्जित करते हुए इस प्रकार पहल को आत्मनिर्भर बनाया गया। यह पहल डॉ. समित शर्मा की अभिनव परिवर्तन लाने के सामर्थ्य, उनके नेतृत्वशीलता के गुणों, दल के सदस्य के रूप में कार्य करने की उनकी शैली पर सबसे अधिक निर्धनों तक पहुंचने की उनकी प्रतिबद्धता चित्रित करती है। चित्तौड़गढ़ के जिलाधीश के रूप में उन्होंने सरकारी चिकित्सकों, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, जिला प्रशासन और वित्त विभाग में कार्यतंत्र के बीच एक सहक्रिया सृजित की।

यह पहल निर्धनों (निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों) तक उन्हें चिकित्सा व्यय के कारण ऋण जाल में फंसने से रोकते हुए पहुंची। दवाईयों की वहनीयता ने उन्हें इच्छापूर्वक चिकित्सा उपचार लेने में सहायता की। चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग 5.1 लाख रोगियों ने

Initiative - Making Medicines Affordable, Chittorgarh, Rajasthan

Name of the Awardee - Dr. Samit Sharma, IAS, then District Magistrate, Chittorgarh, Rajasthan

The project was initiated to bring down the cost of the generic medicines in remote rural villages. Making quality drugs available at Government Cooperative Medical shops - at less than one fourth the price at which they are sold in private medical shops - has revolutionized the way drugs and other surgical instruments are procured, disbursed and sold in the rural areas within the state of Rajasthan.

The highlight of implementation was ensuring accessibility of drugs, through district wide chain of fair price medicine shops, which serve the OPD and 'Indoor patients' of Government Hospitals, and general public as well. The initiative included persuasion of doctors to prescribe generic medicines. Procurement of these generic medicines was done as advised by a team of doctors and certain very prestigeous pharmaceutical companies were empanelled as drug procurement partners. Medicines thus obtained were dispensed, through government-controlled medical stores, at prices much below MRP (at one fourth price) and yet making 20% profit, thus making the initiative self- sustainable. The initiative mirrors Dr. Samit Sharma's ability to innovate, his leadership qualities, his style of functioning as a team player, and above all his commitment to reach out to the poor. As the District Magistrate of Chittorgarh, he created a synergy between the Government doctors, the machinery in the Health Department, Cooperative Department, District Administration and the Finance Dept.

The initiative reached out to the poor (BPL families), preventing them from falling into a debt trap on account of medical expenses. Affordability of medicines has helped them to willingly seek medical treatment. Approximately

कम लागत वाली औषधियां प्राप्त की। इस पहल ने राज्य के राजकोष का व्यय भी कम कर दिया क्योंकि नि:शुल्क प्रदान की गई दवाईयां भी सामान्य औषधि के मूल्यों पर प्राप्त की गई थी। इसने स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली की प्रभोवोत्पादकता बढ़ाते हुए आधी से कम लागत पर सभी सरकारी अस्पतालों में सात दिन चौबीस घंटे नैदानिक परीक्षण सुविधा भी उपलब्ध कराई।

5.1 lakh patients procured low-cost drugs in Chittorgarh district. The initiative brought down the expenditure of state exchequer as the medicines provided free of cost were also procured at the generic drug prices. It also made 24X7 diagnostic test facility available in all Government hospitals at less than half the cost, enhancing the efficacy of health delivery system.

पहल – नदी संयोजन परियोजना, जलगांव, महाराष्ट्र

पुरस्कार विजेता का नाम – श्री विजय सिंघल, भा. प्र. से., तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश, जलगांव, महाराष्ट्र

वर्ष 2005 में जलगांव जिले में अत्यल्प वर्षा हुई जबकि अधिकांश महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे स्थिति का सामना किया जा रहा था। सभी जलाशय खाली हो गए थे और भूजल स्तर घट रहा था, जबकि पड़ोसी नासिक जिले में गिरणा बांध से अतिजल प्रवाह हो रहा था। जलगांव जिला प्रशासन ने गिरणा बांध से अधिक जल को जलगांव के जल की कमी वाले क्षेत्रों में विपथित करने की एक अभिनव नदी संयोजन परियोजना कार्यान्वित की। साझा उद्देश्य अर्थात जल की कमी से निपटने और सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों के लिए जल प्रदान करने हेतु सभी हितधारकों से सहयोग और समर्थन प्राप्त किया गया। परियोजना से प्रभावित भूस्वामी इच्छुक भागीदार बन गए क्योंकि अपनी भूमि का हिस्सा छोड़ने से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धा के कारण भूमि का शेष भाग कृषि योग्य हो जाएगा।

श्री विजय सिंघल ने इस परियोजना की संकल्पना की और सभी हितधारकों के पूर्ण समर्थन से रिकार्ड समय में संकल्पना को वास्तविकता में रूपांतरित करने में नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने ''श्रमदान'' के रूप में स्थानीय समुदायों और ग्रामीणों की सहायता मांगी और सिंचाई विभाग, राज्य सरकार तथा संसद सदस्य/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम निधियों से संसाधन प्रबंधन में सहायक रहे।

इस पहल ने लाभदायी रूप से अधिशेष के क्षेत्रों से अधिक जल का जल की कमी वाले क्षेत्र में उपयोग किया। इस प्रकार, इसने एक नगर निगम, पांच नगर परिषदों और 123 गांवों में लगभग 0.85 मिलियन का आबादी के लिए पेय जल की समस्या का समाधान किया तथा इस तरह टैंकरों द्वारा जलापूर्ति पर व्यय की जाने वाली धनराशि की बचत हुई। इसके परिणामस्वरूप 4,886 एमसीएफटी जल की अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित हुई। लगभग 700 मध्यम, छोटे बांध, ग्राम तालाब और परिस्रवण तालाब भर गए तथा इस नदी संयोजन परियोजना के कारण 16,000 से अधिक कुंए पुनः भर गए। सिंचित क्षेत्र भी वर्ष 2005 में 13,000 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2008 में 30,000 हेक्टेयर तक हो गए।

Initiative - River Linking Project, Jalgaon, Maharashtra

Name of the Awardee - Shri Vijay Singhal, IAS, then Collector & District Magistrate, Jalgaon, Maharashtra

In 2005, Jalgaon district received scant rainfall while most of Maharashtra was experiencing flood-like situation. All water reservoirs were empty and ground water level was depleting, while in the neighboring Nasik district, the Girna dam was overflowing. The Jalgaon district administration implemented an innovative river linking project to divert the excess water from the Girna dam to the water-scarce regions of Jalgaon. Cooperation and support were garnered from all the stakeholders to achieve a common objective, viz. tackling water scarcity and providing water for irrigation and other purposes. The landowners affected by the project became willing partners, as parting with a part of their land would allow the remaining part of the land to be arable on account of availability of water for irrigation.

Shri Vijay Singhal conceived the project and provided leadership in translating the concept into reality in a record time with full support from all stakeholders. He sought the support of the local communities and villagers in the form of 'Shramdaan' and was instrumental in marshalling the resources from the Irrigation Department, State Government and MP/MLA Local Area Development Scheme funds.

The initiative gainfully utilized the excess water from surplus regions in the water deficit regions. It, thus, solved the drinking water problem for a population of about 0.85 million in one municipal corporation, five municipal councils and 123 villages, thus, saving the money spent on supply of water by tankers. It resulted in additional storage capacity of 4,886 Mcft of water. Around 700 medium, small dams, village tanks and percolation tanks were filled and more than 16,000 water wells were recharged because of this river connectivity project. The irrigated area increased from 13,000 hectares in 2005 to 30,000 hectares in 2008.

पहल - गर्भाशय कैंसर की जांच-चेन्नई, तमिलनाडु

पुरस्कार विजेता का नाम – श्री राजेश लखानी, भा. प्र. से., आयुक्त, चेन्नई निगम, तमिलनाडु

मद्रास कैंसर रजिस्ट्री ने वर्ष 2002 में 1,90,000 कैंसर के मामले होने की सूचना दी। यह चेन्नई में विद्यमान अत्यधिक महामारीवैज्ञानिक और सामाजिक दशाओं के कारण था। निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर, खराब जननांग स्वच्छता, शीघ्र विवाह और रोग तथा उपचार के बारे में ज्ञान की कमी के परिणामस्वरूप अपने आय-अर्जन वर्षों में रहने वाली निर्धन महिलाओं को अधिक जोखिम होता है। नगर निगम, चेन्नई द्वारा 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच वाली महिलाओं में गर्भाशय में कैंसर-पूर्व घावों का पता लगाने के लिए महिलाओं के निवारक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया क्योंकि इस बीमारी में पूर्वानुमान और सामयिक उपचार शत-प्रतिशत स्वास्थ्य-लाभ सुनिश्चित करता है।

श्री रोजश लखानी ने विश्व-स्वास्थ्य संगठन अनुमोदित एक लागत और समय प्रभावी (एक आगमन) क्रायोथिरेपी प्रौद्योगिकी की पहचान की और अतिरिक्त प्रशिक्षण के बाद मौजूदा कार्यतंत्र के माध्यम से इसका प्रयोग किया। बहु-प्रयोजनीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एमपीएचडब्ल्यू), जो जांच और अनुवर्ती परीक्षण प्राप्त करने के लिए समुदाय में जाते हैं और लाभार्थियों को जुटाते हैं, के माध्यम से सहक्रियात्मक पहुंच पर बल दिया गया। क्रायोथिरेपी में रोगी का निरंतर अनुवीक्षण और 5 वर्षों की अवधि तक नियमित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल होती है। एक दौरे में ही 9 क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार किया गया। सभी 93 स्वास्थ्य पोस्ट पता लगाने के लिए सज्जित थे।

सभी चिकित्सा कालेज अस्पतालों में किए गए परीक्षणों की संख्या वर्ष 2007-08 में केवल 1230 थी। तथापि, परियोजना-पहल के माध्यम से कवरेज का विस्तार 1 लाख निर्धन सीमांतिक महिलाओं को शामिल करने के लिए किया गया। 18 लाख महिलाओं की कुल आबादी की तुलना में अप्रैल, 2008 और नवम्बर, 2009 के बीच ग्रीवा कैंसर के लिए 1,73,689 महिलाओं की जांच की गई। इनमें से 1579 महिलाएं पॉजिटिव पाई गई और इस प्रकार शीघ्र पता लगने, उपचार और निरंतर अनुवीक्षण के परिणामस्वरूप बच गई। शेष आबादी की जांच की जा रही है। तमिलनाडु सरकार संपूर्ण राज्य में इस पहल को लागू कर रही है।

Initiative - Cervical Cancer Screening, Chennai, Tamil Nadu

Name of the Awardee - Shri Rajesh Lakhani, IAS, Commissioner, Corporation of Chennai, Tamil Nadu

Madras Cancer Registry reported an incidence of 1,90,000 cases of cancer in 2002. This was due to overwhelming epidemiological and social conditions prevalent in Chennai. Poor women in their income-earning years are at high risk as a result of low socio-economic status, poor genital hygiene, early marriage, and lack of knowledge about the disease and treatment. A new program in the area of women's preventive health to detect pre-cancerous lesions in the cervix of women between 18 and 60 was launched by the Municipal Corporation, Chennai as in this disease, prognosis and timely treatment ensures 100% cure.

Shri Rajesh Lakhani identified a cost and time-effective (one visit) WHO-approved cryotherapy technology and applied it through the existing machinery, after additional training. Emphasis was laid on proactive outreach through Multi-Purpose Health Workers (MPHWs), who go into the community and mobilize beneficiaries to avail of screening and follow up test. Cryotherapy involves continuous monitoring of the patient and regular follow up over a period of 5 years. Treatment was given at the 9 zonal health centers, in a single visit. All 93 health-posts were equipped for detection.

The number of tests done in all medical college hospitals was only 1230 in the year 2007-08. However, through the project-initiative, coverage was extended to over 1 lakh poor and marginalized women. Against a total population of 18 lakh women, screening of 1,73,689 women for cervical cancer was completed between April 2008 and November 2009. 1579 women were detected positive and, thus, saved as a result of early detection, treatment and continuous monitoring. The remaining population is being screened. The Government of Tamil Nadu is introducing this initiative all over the State.

पहल – धान की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण, छत्तीसगढ़

दल के सदस्यों के नाम –
1. डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से., तत्कालीन सचिव, एफसीएस एंड सीए विभाग
2. श्री गौरव द्विवेदी, भा. प्र. से., तत्कालीन प्रबंध निदेशक 'मार्कफेड' और 'सीजीएससीएससी'
3. श्री ए.के. सोमशेखर, वैज्ञानिक 'घ', राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

खाद्य प्राप्ति और सार्वजनिक वितरण किसानों और उपभोक्ताओं के हित संरक्षण के लिए भारत सरकार की खाद्य नीति के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लगभग 3.5 माह की अवधि में 7.5 लाख से अधिक किसानों से न्यूनतन समर्थन मूल्य पर प्रति वर्ष 30 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति करता है। इस पहल के भाग के रूप में, धान की अधिप्राप्ति और पीडीएस में शामिल सभी प्रक्रियाएं खाद्य विभाग, छत्तीसगढ़ मार्केटिंग फेडरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (सीजीएससीएससी), भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय सहकारी बैंक जैसे विभिन्न संगठनों को शामिल करते हुए पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की ढुलाई का वेब-आधारित अनुवीक्षण विकसित किया गया है। इसमें, भंडारगारों से उचित मूल्य की दुकानों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की ढुलाई के अनुवीक्षण के लिए जीपीएस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। ट्रक का आवागमन वास्तविक समय में संचलित आईकॉन के रूप में मानचित्र पर दर्शाया जाता है और एक नियंत्रण कक्ष से इसका अनुवीक्षण किया जा सकता है। अगर ट्रक किसी वर्जित क्षेत्र में जाता है तो संबंधित प्राधिकारियों को एसएमएस चेतावनी भेजी जाती है ताकि कार्रवाई की जा सके। यह प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के विपणन को रोकने का एक प्रौद्योगिकी समाधान है।

नागरिक परस्पर-क्रिया वेबसाइट अथवा कॉल सेंटर के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली के माध्यम से अनुवीक्षण किया जाता है। जांच अधिकारी,

Initiative - Computerization of Paddy Procurement and Public Distribution System, Chhattisgarh

Name of the Team Members -

1. Dr. Alok Shukla, IAS, then Secretary, Department of FCS & CA
2. Shri Gaurav Dwivedi, IAS, then Managing Director, 'MARKFED' & 'CGSCSC'
3. Shri A.K.Somasekhar, Scientist 'D', National Informatics Centre

Food procurement and public distribution are two important pillars of food policy of Government of India, for protecting farmers and consumers interests. The State of Chhattisgarh (CG) procures over 30 Lakh Metric Tonnes of Paddy every year on Minimum Support Price (MSP) from more than 7.5 Lakh farmers over a period of about 3.5 months. As a part of this initiative, all processes involved in paddy procurement and PDS have been fully computerized involving different organizations like Department of Food, CG Marketing Federation, CG State Civil Supplies Corporation (CGSCSC), Food Corporation of India, and Central Cooperative Bank.

Web-based monitoring of transportation of PDS commodities at Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation headquarters has been developed. In this, the GPS technology is used to monitor transportation of PDS commodities from warehouses to FPS. The movement of the truck is shown on a map as a moving icon in real time and can be monitored from the control room. If the truck goes to a geofenced area, SMS alarms are sent to the concerned authorities so that action can be taken. The system is a technological solution to check diversion of PDS commodities.

The complaints lodged through citizen interface website or call centre are monitored through a Complaint Monitoring System. Details of enquiry Officer,

उसकी रिपोर्ट और केंद्रों द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रणाली में प्रविष्ट किए जाते हैं।

धान की अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन्नयन के लिए दल द्वारा की गई पहल ने पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार दूर करने और सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी में सहायता की। एकीकृत राशन कार्ड डाटाबेस रखने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों को जारी करने में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती हैं, जिसमें सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड रखने और अपने संबंधित राशन की दुकानों में वस्तुएं उपलब्ध कराने में अपने अधिकारों का उपयोग करना सुविधाजनक हुआ।

ऐसे समय जब सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी प्रणाली की प्रभावोत्पादकता वर्धित रूप से जांच के अधीन आ रही है और सेवा सुपुर्दगी सुधारने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी को एकमात्र विकल्प के रूप में माना जा रहा है, दल ने इस पहल के माध्यम से ग्रामीण निध र्नों तक पहुंचने में सरकारी संस्थाओं की निरंतर संगतता स्थापित की है।

his report, and action taken by the centres are entered in the system by concerned authority.

The initiative by the team for upgradation of paddy procurement and Public Distribution System (PDS) helped to increase transparency, eliminate corruption and people's participation at all levels. Transparency is also ensured in maintaining Unified Ration Card Database and Issue of PDS commodities to FPS, which facilitated all the eligible households to utilise their right to have a ration card and also commodities available at their respective ration shop.

At a time when the effectiveness of public service delivery system is increasingly coming under scrutiny and Public Private Partnerships (PPPs) are being touted as the only option to improve service delivery, the team, through this initiative has established the continuing relevance of government institutions in reaching out to the rural poor.

पहल – वन अधिकारों को मान्यता, मध्य प्रदेश

दल के सदस्यों के नाम –

1. श्री ओ. पी. रावत, भा. प्र. से., प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार
2. श्री जयदीप गोविंद, भा. प्र. से., तत्कालीन आयुक्त, जनजाति विकास
3. श्री अनिल ओबरॉय, भा. व. से., अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
4. सुश्री रश्मि अरूण शामी, भा. प्र. से., तत्कालीन निदेशक, जनजाति क्षेत्र विकास आयोजना
5. श्री अशोक कुमार उपाध्याय, अपर निदेशक

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 से लागू हुआ था। यह सुनिश्चित करने कि जनजाति और पारम्परिक वन निवासी वन संसाधनों के लिए हकदारी प्राप्त करें और निहित स्वार्थों द्वारा शोषण से उन्हें सुरक्षित किया जाए, के उद्देश्य से अधिनियम को कार्यान्वित करने की पहल मध्य प्रदेश में जनवरी, 2008 में प्रारंभ की गई।

राज्य सरकार जनजाति कल्याण विभाग ने अपने विभाग की सहायता से अधिकारियों के उपर्युक्त दल के अनुरोध पर ''वन निवासियों का सर्वेक्षण'' नामक एक बहुत विस्तृत सॉफ्टवेयर विकसित किया। यह सॉफ्टवेयर ''प्रयोक्ता'' को प्रत्येक लाभार्थी का आंकड़ा प्रविष्ट करने में सहायता करता है। सॉफ्टवेयर जिला–वार/प्रखंड–वार पूर्ण एमआईएस सूचना भी प्रदान करता है। उपर्युक्त सभी सूचना प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एक वेबसाइट पर रखी जाती है। राज्य सरकार ने दावेदारों की भू–धारिता के अंकीय भू–मानचित्रण के लिए वैयक्तिक अंकीय सहायक (पीडीए), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और वैश्विक स्थिति प्रणाली (जीपीएस) का प्रयोग किया। इसने जनजाति समुदायों के सर्वेक्षण

Initiative - Recognition of Forest Rights, Madhya Pradesh

Name of the Team Members -

1. Shri O.P. Rawat, IAS, Principal Secretary, Govt. of Madhya Pradesh
2. Shri Jaideep Govind, IAS, then Commissioner, Tribal Development.
3. Shri Anil Oberoi, IFS, Addl. Principal Chief Conservator of Forest
4. Ms. Rashmi Arun Shami, IAS, then Director, Tribal Area Development Planning.
5. Shri Ashok Kumar Upadhyay, Additional Director

The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 was brought into effect on December 31, 2007. The initiative to implement the Act with the objective to ensure that the tribals and traditional forest-dwellers received the entitlement to forest resources, and were protected from exploitation by vested interests, was undertaken in January, 2008 in Madhya Pradesh.

The Tribal Welfare Department of the State Government, with the help of its Forest Department developed a very detailed software called "Survey of Forest Dwellers" at the instance of the above team of officers. This software helps the 'Users' in entering the data of each beneficiary. The software also gives complete District wise/Block wise MIS information. All the above information is placed on a website to make the system transparent. The State Government used the personal digital assistant (PDA), Geographical Information System (GIS) and Global Positioning System (GPS) for digital geo-mapping of land holdings of the claimants. This facilitated the survey of tribal communities and the creation of a database

और जिला–स्तर पर डाटाबेस के सृजन को सुविधाजनक बनाया, जिससे कार्यान्वयन निम्न लागत पर बहुत सक्षम और अतिशीघ्र हो सका।

दिनांक 31.03.2009 की यथास्थिति, राज्य सरकार ने 3, 29, 184 दावे प्राप्त किए। इसने 13,060 दावों का निपटान किया और वितरण के लिए तैयार हकदारी विलेखों की संख्या 32,419 थी। वह तरीका, जिससे केंद्रीय अधिनियम कार्यान्वित किया गया, ने राज्य सरकार को पर्याप्त निधियों की बचत कराते हुए इसे बहुत लागत प्रभावी बनाया। निरक्षर जनजाति आबादी को सुग्राही बनाने और उनके द्वारा कब्जा किए हुए वन भूमि को नियमित करने की इच्छा रखने के लिए उन तक पहुंचने हेतु सरकार को सफल प्रयासों का साक्ष्य बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदन पत्रों से मिलता है। बड़े पैमाने पर ऐसा कार्यान्वयन कोई शिकायत प्राप्त किए बिना जा सका।

at the district level, making the implementation very efficient and expeditious at a very low cost.

As on 31-3-2009, the State Government received 3,29,184 claims. It had disposed 13,060 claims and title deeds ready for distribution were 32,419. The manner, in which the Central Act was implemented, made it very cost-effective, saving substantial funds to the state government. The government's successful efforts to reach out to the illiterate tribal population in sensitizing and in intending to regularize forestland occupied by them are evidenced by large number of applications. Such large-scale implementation could be achieved without any complaints from any quarter.

पहल – समन्वित करदाता आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार

दल के सदस्यों के नाम –

1. श्री एस.एस. खान, भा. रा. से. (आई.टी.), तत्कालीन आयकर महानिदेशक (जांच), नई दिल्ली
2. श्री मिलाप जैन, भा. रा. से. (आई.टी.), आयकर महानिदेशक (जांच), नई दिल्ली
3. श्री जी.टी. वेंकटेश्वर राव, भा. रा. से. (आई.टी.), तत्कालीन आयकर अपर निदेशक (जांच), नई दिल्ली

इस पहल में जो भी थोड़ा आंकड़ा उपलब्ध हो, उसके आधार पर नाम और पते का मिलान करने के लिए ''मिप्रा''–मल्टी–इंटरेटिव फोनेटिक पैटर्न रिकॉगनिशन एल्गोरिथ्म नामक एक सॉफ्टवेयर सर्च–इंजन (परिदृश्य टूल) विकसित करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बौद्धिक प्रयोग शामिल था। यह सूचना को कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता में परिवर्तित करता है।

यह साधन एक प्रभावी और गैर–अंतर्वेधी जांच कार्यतंत्र है। सॉफ्टवेयर की शक्ति एक ही करदाता के लेन–देनों के पहचान योग्य समूहों के सृजन में निहित है। सभी किस्मों की फाइल/आंकड़ा संरचना पर कार्यवाही करने के लिए एक पूरक ईटीएल साधन (निष्कर्षण, रूपांतरण और भार) विकसित किया गया। सर्च के पैरामीटरों को प्रचलित बनाया गया। इसमें वर्षों की सीमा, मूल्य और लेन–देनों की मात्रा, संगठन के गठन आदि की पसंद करने की सुविधा है। दल ने विभिन्न डाटाबेस में उपलब्ध बड़ी मात्रा में आंकड़ों और सूचना को कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता में परिवर्तित करने की पहल की। यह नवीन, अद्वितीय और अभिनव परिवर्तन लाने वाले साधन की संकल्पना, डिजाइन, विकास (एक बाह्य एजेंसी की सहायता से) और कार्यान्वयन का अनुरक्षण दल द्वारा किया जा रहा है।

Initiative - Integrated Taxpayer Data Management System (ITDMS), Central Board of Direct Taxes, Government of India

Name of the Team Members -

1. Shri S. S. Khan, IRS (IT),then Director General of Income Tax (Investigation), New Delhi
2. Shri Milap Jain, IRS (IT), Director General of Income Tax (Investigation), New Delhi
3. Shri G. T. Venkateswara Rao, IRS (IT), then Additional Director of Income tax (Investigation), New Delhi

This initiative involved intelligent use of the Information & Communication Technologies (ICT) to develop a software search-engine (a profiling tool) called MIPPRA – Multi-Iterative Phonetic Pattern Recognition Algorithm – for matching names and addresses, based on whatever (little) data is available. It converts information into actionable intelligence.

The tool is an effective and non-intrusive investigation mechanism. The power of the software lay in the creation of identifiable groups of transactions of same taxpayer. A complementary ETL tool (Extract, Transform and Load) was developed to handle all types of file/data structures. Search parameters were made customizable. It has a choice of range of years, value and volume of transactions, constitution of the entity etc. The team took the initiative of converting huge mass of data and information available in different databases into actionable intelligence. The novel, unique and innovative tool is conceptualized, designed, developed (with the help of an outside agency), implemented and is being maintained by the team.

यह साधन विभिन्न डाटाबेस से शीघ्रतापूर्वक सूचना खोजने और संगठन की एकीकृत रूपरेखा सृजित करने में समर्थ है। यह असामान्य और/अथवा उच्च मात्रा और/अथवा उच्च मूल्य का लेन–देन करने वाले करदाताओं और समूहों को अलग करना सुविधाजनक बना रहा है। अभिज्ञात समूहों का उनके वास्तविक कर भुगतान के आंकड़ों से मिलान इस साधन द्वारा संभव बनाया गया बौद्धिक नियंत्रण कार्यतंत्र है। यह साधन सफलतापूर्वक विभिन्न ढांचे और रूपों में विभिन्न स्रोतों से आंकड़ों के हस्तचलित संग्रहण और विश्लेषण में शामिल कठिनाई और मेहनत को दूर करने में विभाग की सहायता करता है।

Category – Team

The tool is able to quickly source information from across different databases and create an integrated profile of the entity. It is facilitating isolation of taxpayers and groups having abnormal and/or high volume and/or high value of transactions. Matching of the identified groups with the data of their actual tax payments is an intelligent control mechanism made possible by the tool. The tool successfully helps the department overcome the difficulty and drudgery involved in manual collection and analysis of data from different sources in different structures and formats.

पहल - ''प्रोजेक्ट एरो'' - भारतीय डाक की कायापलट

संगठन का नाम - डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

''प्रोजेक्ट एरो'' भारतीय डाक का सुधार करने सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और देश भर में चयनित डाकघरों के प्रति लोगों का अनुभव सुधारने के लिए अभिनव एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में अप्रैल, 2008 में प्रारंभ किया गया। चरण-I के दौरान 50 डाकघरों का चयन किया गया था और दिसम्बर, 2008 में समाप्त चरण-II में 450 डाकघरों को शामिल किया गया। 500 डाकघरों को शामिल करते हुए चरण -III का कार्य चल रहा है। अभिनव परिवर्तन में प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाएं और चार क्षेत्रों से संबद्ध सुरूचिपूर्णता; डाक सुपुर्दगी, बचत बैंक, प्रेषण और सेवा स्तरों को प्रक्रियाओं के यौक्तिकीकरण और अंकीकरण तथा अनुवीक्षण और पर्यवेक्षण प्रणाली जिसमें हितधारक शामिल हों, के माध्यम से सुधारने के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है। डाकघरों के ''देखने और महसूस करने'' को सुधारने के लिए अभिनव परिवर्तन में मानव संसाधन, ब्रांडिंग प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में निविष्टियां शामिल हैं।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सभी-ई-समर्थ सेवाएं प्रदान करना था ताकि डाकघर आम आदमी के लिए ''विश्व दर्शन की खिड़की'' बन जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी डाक प्रचालन सरल-सुगम तरीके से होते हैं और प्रचालन में कम समय लगता है, सूचना और प्रौद्योगिकी समर्थ साधनों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ा निष्कर्षण साधन पर आधारित एक वेब-आधारित अनुवीक्षण प्रणाली, कार्यनिष्पादन डैशबोर्ड कार्यान्वित की गई है। एक अधिकृत रिपोर्ट, जिसने ''क्या किया जाना है'' प्रलेखबद्ध किया, प्रकाशित की गई, जिसमें सभी सर्वोत्तम पद्धतियों का सारांश दिया गया है। मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों (केपीआई) की तुलना में कार्यनिष्पादन का अनुवीक्षण ''प्रोजेक्ट एरो'' की सफलता की कुंजी है।

''प्रोजेक्ट एरो'' का अनुभव डाकघरों में एकीकृत सुधार लाने के लिए एक कार्यकरण मॉडल है ताकि ग्राहक अंतर महसूस कर सकें। प्रयोग के लिए चुने गए 50 डाकघरों की बाह्य लेखापरीक्षा से पंजीकृत पत्रों के कार्यनिष्पादन में 99 प्रतिशत, साधारण डाक के लिए 94-100 प्रतिशत, स्पीड पोस्ट में 89-99 प्रतिशत और धनादेशों के लिए 100 प्रतिशत

Initiative - 'Project Arrow' - Transforming India Post

Name of the Organisation: - Department of Posts, Ministry of Communications & IT, Government of India

'Project Arrow' was launched in April 2008 as an innovative integrated approach to reforming India Post and enhancing the quality of services and improving peoples' experience of select post offices around the country. 50 post offices were selected during Phase-1, and 450 were covered in Phase-2 ending in December 2008. Phase-3 covering 500 post offices is in progress. Innovations include integrated approach to improving technology, processes, and aesthetics related to four areas: mail delivery, savings bank, remittances, and service levels through streamlining and digitization of processes and monitoring and supervision systems that involve stakeholders. Innovations to improve the 'look and feel' of the post offices include inputs into human resources, branding, technology, and infrastructure.

The objective of this project was to provide all e-enabled services so that post offices become a 'Window to the World' for the Aam Aadmi. IT-enabled reliable tools are used to ensure that all postal operations are smoothly carried out and less time is consumed by back-end operations. Performance Dashboard, a web-based monitoring system based on Data Extraction Tool has been implemented. A Blue Book, which documented What is to be done was brought out wherein all the best practices were summarized. Monitoring performance against the Key Performance Indications (KPIs) is the key to the success of Project Arrow.

The 'Project Arrow' experience is a working model for bringing an integrated improvement in the post office so that customers can feel the difference. External audit of 50 post offices chosen for pilot revealed 99% improvement in registered letter performance, 94-100% for ordinary mail, 89-99% speed post, and 100% for money orders. Average customer satisfaction score

दिनांक 21 अप्रैल, 2010 को प्रदान किए गए वर्ष 2008-09 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

1.	**पहल** –	**ढ़ाँचों का अतिक्रमण हटाना सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना, जबलपुर, मध्य प्रदेश**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री संजय दुबे, भा. प्र. से., तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश, जबलपुर, मध्य प्रदेश
2.	**पहल** –	**नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी, बालाघाट, मध्य प्रदेश**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री गुलशन बामरा, भा. प्र. से., तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश, बालाघाट मध्य प्रदेश
3.	**पहल** –	**औषधियों को किफायती बनाना, चित्तौड़गढ़, राजस्थान**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	डॉ. समित शर्मा, भा. प्र. से., तत्कालीन जिलाधीश चित्तौड़गढ़, राजस्थान
4.	**पहल** –	**नदी संयोजन परियोजना, जलगांव, महाराष्ट्र**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री विजय सिंघल, भा. प्र. से., तत्कालीन समाहर्ता और जिलाधीश, जलगांव, महाराष्ट्र

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration for the year 2008-09 presented on 21st April, 2010

1.	**Initiative-**	**Removal of Encroachments of Structures - Maintaining Communal Harmony, Jabalpur, Madhya Pradesh**
	Name of the Awardee:	Shri Sanjay Dubey, IAS then Collector & District Magistrate, Jabalpur, Madhya Pradesh
2.	**Initiative-**	**Involvement of Community in Naxalite-affected Areas, Balaghat, Madhya Pradesh**
	Name of the Awardee:	Shri Gulshan Bamra, IAS, then Collector and District Magistrate, Balaghat, Madhya Pradesh
3.	**Initiative-**	**Making Medicines Affordable, Chittorgarh, Rajasthan**
	Name of the Awardee:	Dr. Samit Sharma, IAS, then District Magistrate, Chittorgarh, Rajasthan
4.	**Initiative-**	**River Linking Project, Jalgaon, Maharashtra**
	Name of the Awardee:	Shri Vijay Singhal, IAS, then Collector & District Magistrate, Jalgaon, Maharashtra

5.	**पहल –**	**गर्भाशय कैंसर की जांच– चेन्नई, तमिलनाडु**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री राजेश लखानी, भा. प्र. से., आयुक्त, चेन्नई निगम, तमिलनाडु
6.	**पहल –**	**धान की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण, छत्तीसगढ़**
	दल के सदस्यों के नाम :	1. डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से., तत्कालीन सचिव, एफसीएस एंड सीए विभाग 2. श्री गौरव द्विवेदी, भा. प्र. से., तत्कालीन प्रबंध निदेशक, 'मार्कफेड' और 'सीजीएससीएससी' 3. श्री ए.के. सोमशेखर, वैज्ञानिक 'घ' राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र
7.	**पहल –**	**वन अधिकारों को मान्यता, मध्य प्रदेश**
	दल के सदस्यों के नाम :	1. श्री ओ. पी. रावत, भा. प्र. से., प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार 2. श्री जयदीप गोविंद, भा. प्र. से., तत्कालीन आयुक्त, जनजाति विकास 3. श्री अनिल ओबरॉय, भा. प्र. से., अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

5.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Cervical Cancer Screening, Chennai, Tamil Nadu** Shri Rajesh Lakhani, IAS Commissioner, Corporation of Chennai, Tamil Nadu
6.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Computerization of Paddy Procurement and Public Distribution System, Chhattisgarh** 1. Dr. Alok Shukla, IAS, then Secretary, Department of FCS & CA 2. Shri Gaurav Dwivedi, IAS then, Managing Director, 'MARKFED' & 'CGSCSC' 3. Shri A.K. Somasekhar, Scientist 'D', National Informatics Centre
7.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Recognition of Forest Rights, Madhya Pradesh** 1. Shri O.P. Rawat, IAS, Principal Secretary, Govt. of Madhya Pradesh 2. Shri Jaideep Govind, IAS, then Commissioner, Tribal Development. 3. Shri Anil Oberoi, IFS, Addl. Principal Chief Conservator of Forest

		4. सुश्री रश्मि अरूण शामी, भा. प्र. से. तत्कालीन निदेशक, जनजाति क्षेत्र विकास आयोजना 5. श्री अशोक कुमार उपाध्याय, अपर निदेशक
8.	**पहल –** दल के सदस्यों के नाम :	**समन्वित करदाता आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार** 1. श्री एस.एस. खान, भा. रा. से. (आई.टी) तत्कालीन आयकर महानिदेशक (जॉच), नई दिल्ली 2. श्री मिलाप जैन, भा. रा. से. (आई.टी.) आयकर महानिदेशक (जांच), नई दिल्ली 3. श्री जी.टी. वेंकटेश्वर राव, भा. रा. से. (आई.टी.), तत्कालीन आयकर अपर निदेशक (जांच) नई दिल्ली
9.	**पहल –** संगठन का नाम :	**''प्रोजेक्ट एरो''– भारतीय डाक की कायापलट** डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

		4. Ms. Rashmi Arun Shami, IAS, then Director, Tribal Area Development Planning. 5. Shri Ashok Kumar Upadhyay, Additional Director
8.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Integrated Taxpayer Data Management System (ITDMS), Central Board of Direct Taxes, Government of India** 1. Shri S. S. Khan, IRS (IT), then Director General of Income Tax (Investigation), New Delhi 2. Shri Milap Jain, IRS (IT), Director General of Income Tax (Investigation), New Delhi 3. Shri G. T. Venkateswara Rao, IRS (IT), then Additional Director of Income Tax (Investigation), New Delhi
9.	**Initiative-** Name of the Organisation:	**'Project Arrow'- Transforming India Post** Department of Posts, Ministry of Communications & IT, Government of India

दिनांक 21 अप्रैल, 2009 को प्रदान किए गए वर्ष 2007-08 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

1.	**पहल** -	**बंगलौर महानगर परिवहन निगम, कर्नाटक को वित्तीय सहायता**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, भा. प्र. से., तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बंगलौर महानगर परिवहन निगम, कर्नाटक सरकार
2.	**पहल** -	**प्राथमिक शिक्षा हेतु क्रिया आधारित विद्यार्जन (एबीएल) प्रणाली, तमिलनाडु**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री एम. पी. विजय कुमार, भा. प्र. से. तत्कालीन आयुक्त, चैन्नई नगर निगम तमिलनाडु सरकार
3.	**पहल** -	**युद्ध के दौरान बेरूत से भारतीय नागरिकों का निकास**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्रीमती नेंगचा ल्होबुम, भा. वि. से. लेबनान में भारत की राजदूत
4.	**पहल** -	**सुरक्षित मातृत्व एवं बाल संरक्षण कार्यक्रम**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	डॉ. अमरजीत सिंह, भा. प्र. से. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, गुजरात सरकार

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration for the year 2007-08 presented on 21st April, 2009

1.	**Initiative-**	**Financial Sustainability of Bangalore Metropolitan Transport Corporation, Karnataka.**
	Name of the Awardee:	Shri Upendra Tripathy, IAS then Managing Director, Bangalore metropolitan Transport Corporation, Government of Karnataka
2.	**Initiative-**	**Activity Based Learning (ABL) Methodology for Primary Education, Tamil Nadu**
	Name of the Awardee:	Shri M.P.Vijaya Kumar, IAS, then Commissioner of Chennai Municipal Corporation, Government of Tamil Nadu
3.	**Initiative-**	**Evacuation of Indian Nationals from Beirut during the war**
	Name of the Awardee:	Mrs. Nengcha Lhouvum, IFS Ambassador of India in Lebanon
4.	**Initiative-**	**Safe Motherhood and Child Survival Programme**
	Name of the Awardee:	Dr. Amarjit Singh, IAS Secretary, Health & Family Welfare Department, Government of Gujarat

5.	**पहल** – दल के सदस्यों के नाम :	**स्कोर : बिहार में ई-पंजीकरण** 1. श्री अनिल कुमार, भा. प्र. से., आईजी, पंजीकरण 2. श्री दिलीप कुमार, एआईजी पंजीकरण 3. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह 4. श्री बरूणा नंदन सिंह 5. श्री निर्मल किशोर प्रसाद, एसएसए 6. श्री संजय कुमार, एसएसए, बिहार सरकार
6.	**पहल** – दल के सदस्यों के नाम : दल के सदस्यों के नाम :	**एमसीए 21-एक नई-गवर्नेंस परियोजना** 1. श्री अनिल कुमार, भा. प्र. से., 1. श्री अनुराग गोयल, भा. प्र. से. सचिव, एमसीए 2. श्री युद्धवीर सिंह मलिक, भा. प्र. से., तत्कालीन संयुक्त सचिव, एमसीए 3. डॉ. (सुश्री) शीला भिडे, भा. प्र. से., तत्कालीन संयुक्त सचिव, एमसीए 4. श्री आर. चंद्रशेखर, भा. प्र. से. तत्कालीन अपर सचिव (आई.टी.) 5. श्री जितेश खोसला, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, एमसीए 6. श्री एस. श्रीधरन, कनिष्ठ विश्लेषक, एमसीए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

5.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**SCORE: e-Registration in Bihar** 1. Shri Anil Kumar, IAS, IG Registration 2. Shri Dilip Kumar, AIG Registration 3. Shri Birendra Kumar Singh 4. Shri Baruna Nandan Singh 5. Shri Nirmal Kishor Prasad, SSA 6. Shri Sanjay Kumar, SSA Government of Bihar
6.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**MCA21 – an e-Governance Project** 1. Shri Anurag Goel, IAS, Secretary, MCA 2. Shri Yudhvir Singh Malik, IAS, then JS, MCA 3. Dr.(Ms.) Sheela Bhide, IAS, then JS, MCA 4. Shri R.Chandrashekhar, IAS, then AS (IT) 5. Shri Jitesh Khosla, IAS, JS, MCA 6. Shri S.Sridharan, JA, MCA, Ministry of Corporate Affairs, Government of India

7.	**पहल** – दल के सदस्यों के नाम :	**बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभ्यास, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़** 1. डॉ. रोहित यादव, भा. प्र. से., जिला अधिकारी 2. सुश्री रितु सेन, भा. प्र. से., जिला अधिकारी (डी एवं आर) जिला: सरगुजा, छत्तीसगढ़ सरकार
8.	**पहल** – दल के सदस्यों के नाम :	**मणिपुर में कार्मिक सूचना प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण** 1. श्री जरनैल सिंह, भा. प्र. से., तत्कालीन प्रधान सचिव 2. श्री आर. आर. रश्मि, भा. प्र. से. 3. श्री एस. सुंदरलाल सिंह, भा. प्र. से. 4. श्री के. राधाकुमार सिंह, भा. प्र. से. 5. श्रीमती एम. बुद्धिमाला देवी 6. श्रीमती ओ. शालिजा चनु मणिपुर सरकार
9.	**पहल** – संगठन का नाम :	**जोखिम प्रबंध प्रणाली (आरएमएस) का कार्यान्वयन** प्रणाली तथा आँकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय केंद्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड, भारत सरकार

7.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Improved Health and Sanitation Practices, District Surguja, Chhattisgarh** 1. Dr. Rohit Yadav, IAS, District Collector 2. Ms. Ritu Sain, IAS, DC (D&R) District : Surguja, Government of Chhattisgarh
8.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Computerization of Personnel Information System in Manipur** 1. Shri Jarnail Singh, IAS, then Chief Secretary 2. Shri R.R.Rashmi, IAS 3. Shri S.Sunderlal Singh, IAS 4. Shri K. Radhakumar Singh, IAS 5. Smt. M.Budhimala Devi 6. Smt. O.Shaliza Chanu Government of Manipur
9.	**Initiative-** Name of the Organisation:	**Implementation of the Risk Management System(RMS)** Directorate General of Systems & Data Management, Central Board of Excise and Customs, Government of India

दिनांक 21 अप्रैल, 2008 को प्रदान किए गए वर्ष 2006-07 हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

1.	**पहल** -	**त्रिची सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	श्री जे.के. त्रिपाठी, भा. पु. से., पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध स्कन्ध तमिलनाडु सरकार
2.	**पहल** -	**मातृत्व एवं बाल संरक्षण तथा स्वास्थ्य में सुधार करना (तमिलनाडु)**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	सुश्री शीला रानी चुकंट, भा. प्र. से., अध्यक्ष तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड
3.	**पहल** -	**ठाणे एवं नागपुर (महाराष्ट्र) शहरों का बदला स्वरूप**
	पुरस्कार विजेता का नाम :	डॉ. टी. चन्द्रशेखर, भा. प्र. से., उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई
4.	**पहल** -	**लोकवाणी-नागरिकों को अधिकारिता देने का एक प्रयास (उत्तर प्रदेश)**
	दल के सदस्यों का नाम :	(i) श्री आमोद कुमार, भा. प्र. से. (ii) सुश्री जोहरा चटर्जी, भा. प्र. से. (iii) श्री एस.बी. सिंह

Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration for the year 2006-07 presented on 21st April, 2008

1.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Trichy Community Policing** Shri J.K.Tripathy, IPS Inspector General of Police Economic Offences Wing Government of Tamil Nadu
2.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Improving Maternal and Child Survival and Health (Tamil Nadu)** Ms. Sheela Rani Chunkath, IAS Chairperson, Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.
3.	**Initiative-** Name of the Awardee:	**Changing Face of Thane & Nagpur Cities (Maharashtra)** Dr. T.Chandra Shekar, IAS Vice President & CEO, Maharashtra Housing & Area Development Authority, Mumbai
4.	**Initiative-** Name of the Team Members :	**Lokvani-an effort to empower the Citizen (Uttar Pradesh)** (i) Shri Amod Kumar, IAS (ii) Ms. Zohra Chaterjee, IAS (iii) Shri SB Singh

		(iv) श्री उमा शंकर सिंह (v) श्री देवेन्द्र पाण्डे (vi) श्री ए.पी. सिंह
5.	**पहल** – दल के सदस्यों का नाम :	**सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा पहल** (i) श्री गौतम गुहा, भा.ले. तथा ले.प. सेवा (ii) श्री एल.एस. सिंह, भा.ले. तथा ले.प. सेवा (iii) श्री राजेश गोयल, भा.ले. तथा ले.प. सेवा (iv) श्री नीलेश कुमार शाह, भा.ले. तथा ले.प. सेवा (v) डॉ. आशुतोष शर्मा, भा.ले. तथा ले.प. सेवा
6.	**पहल** – दल के सदस्यों का नाम :	**संरक्षित क्षेत्रों का कारगर प्रबंधन–उत्तराखंड** (i) सुश्री ज्योत्सना स्टिलिंग, भा.वन.से. (ii) श्री ए.के. बनर्जी, भा.वन. से.
7.	**पहल** – दल के सदस्यों का नाम :	**अनारक्षित टिकट प्रणाली– रेल मंत्रालय** 1. श्री विक्रम चोपड़ा, आई आर टी एस 2. डॉ. राजेश नारंग 3. श्री टी वेंकटसुब्रमणियन् आईआरएसएमई 4. श्री आर चन्द्रशेखर 5. श्री रमन बंसल 6. सुश्री मोनिका मल्होत्रा 7. श्री आलोक चतुर्वेदी आई आर टी एस

		(iv) Shri Uma Shankar Singh (v) Shri Devendra Pande (vi) Shri A P Singh
5.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Information Technology Audit Initiative** (i) Shri Gautam Guha, IA&AS (ii) Shri L S Singh, IA&AS (iii) Shri Rajesh Goel, IA&AS (iv) Shri Neelesh Kumar Sah, IA&AS (v) Dr. Ashutosh Sharma, IA&AS
6.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Effective Management of Protected Areas – Uttarakhand** (i) Ms. Jyotsna Sitling, IFS (ii) Shri A.K.Banerjee, IFS
7.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Unreserved Ticketing System – Ministry of Railways** 1. Shri Vikram Chopra, IRTS 2. Dr. Rajesh Narang 3. Shri T. Venkatasubramanian IRSME 4. Shri R.Chandrashekar 5. Shri Raman Bansal 6. Ms. Monica Malhotra 7. Shri Alok Chaturvedi IRTS

		8. श्री टी किरण कुमार 9. श्री कौस्तव मंडल 10. श्री देबाशीष घोष 11. श्री जी.जे. जैरी औरिक सिंह 12. श्री कपिल भगत 13. श्री प्रोजिनेश विस्वास 14. श्री दिलीप मिश्रा 15. श्री संदीप कुमार वत्स 16. श्री आशीष अरोड़ा 17. श्री गौरव डी. जौहरी 18. श्री नितिन गोयल 19. श्री पंकज कुमार 20. श्री आशीष विश्वकर्मा 21. श्री गौरव जैन 22. श्री बालू लाल धाकड़ 23. श्री रीतेश लाल 24. श्री प्रेम कुमार 25. श्री महेन्दर जे. दुबे 26. श्री मोहम्मद शाहिद 27. श्री अंजनी कुमार मलिक 28. श्री दर्शन
8.	**पहल** – दल के सदस्यों के नाम :	**राजर्षि शाहू सर्वांगीण कार्यक्रम, जिला परिषद्, कोल्हापुर, महाराष्ट्र** (i) श्री देशमुख प्रभाकर कृष्ण जी, भा.प्र.से. (ii) श्री माने महावीर दामोदर

		8. Shri T.Kiran Kumar 9. Shri Kaustav Mandal 10. Shri Debashish Ghosh 11. Shri G.J.Jerrie Auric Singh 12. Shri Kapil Bhagat 13. Shri Projinesh Biswas 14. Shri Dileep Mishra 15. Shri Sandeep Kumar Vats 16. Shri Ashish Arora 17. Shri Gaurav D. Johari 18. Shri Nitin Goyal 19. Shri Pankaj Kumar 20. Shri Ashish Vishwakarma 21. Shri Gaurav Jain 22. Shri Balu Lal Dhaker 23. Shri Ritesh Lal 24. Shri Prem Kumar 25. Shri Mahender J Dubey 26. Shri Mohd. Shahid 27. Shri Anjani Kumar Malik 28. Shri Darshan
8.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Rajarshi Shahu Sarvangin Karyakram, Zilla Parishad, Kolhapur, Maharashtra** (i) Shri Deshmukh Prabhakar-Krishnaji,IAS (ii) Shri Mane Mahavir Damodar

9.	**पहल –** दल के सदस्यों के नाम :	**दिल्ली सरकार विद्यालय पद्धति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में मूलभूत सुधार** (i) श्री राजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (ii) श्री विजय कुमार, भा.प्र.से. (iii) श्रीमती गीतांजली जी कुन्द्रा, भा.प्र.से. (iv) श्री अशोक कुमार
10.	**पहल –** दल के सदस्यों के नाम :	**जम्मू और कश्मीर राज्य में भूकम्प की आपातिक स्थिति में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन** (i) श्री बी.बी. व्यास, भा.प्र.से. (ii) श्री बशरत अहमद धर, भा.प्र.से (iii) श्री बशीर अहमद रुनियाल, भा.प्र.से. (iv) श्री अब्दुल मजीद खाण्डेय, क.प्र.से. (v) श्री जयपाल सिंह, क.प्र.से. (vi) श्री सईद शरीफ-उद्-दीन, क.प्र.से. (vii) श्री मोहम्मद रमजान ठाकुर, क.प्र.से.
11.	**पहल –**	**जल और स्वच्छता प्रबंध संगठन (डब्ल्यू ए एस एम ओ) – ''गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम भागीदारी पेय जल प्रदायगी पहुंच'' –गुजरात सरकार**

9.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Radical Improvement in Delhi Government School System, Government of NCT of Delhi** (i) Sh. Rajendra Kumar, IAS (ii) Sh. Vijay Kumar, IAS (iii) Smt. Gitanjali G Kundra, IAS (iv) Sh. Ashok Kumar
10.	**Initiative-** Name of the Team Members:	**Extraordinary Performance in Emergent Situation of Earthquake in the State of J&K.** (i) Shri B.B.Vyas, IAS (ii) Shri Basharat Ahmad Dhar, IAS (iii) Shri Bashir Ahmad Runiyal, IAS (iv) Shri Abdul Majid Khanday, KAS (v) Shri Jai Pal Singh, KAS (vi) Shri Syed Sharief-ud-din, KAS (vii) Shri Mohammad Ramzan Thakur, KAS
11.	**Initiative-**	**Water & Sanitation Management Organisation (WASMO) – 'Innovative Participatory Drinking Water Delivery Approach in Rural Areas of Gujarat' – Government of Gujarat**